कृषि तकनीकों का विकास

2446. डा० जितेन्द्र कुमार जैन :
श्री वीरेन जे० शाह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस शताब्दी के अन्त तक खाद्यान्न की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में लगभग 240 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्न के उत्पादन की प्राप्ति हेतु कृषि के वर्तमान तकनीकों को विकसित करने की अत्यावश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने इस देश की आवश्यकता और इसके पर्यावरण के अनुसार तकनीकों को विकसित करने में कोई प्रगति की है; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ग्राम किसानों को ये तकनीकें उपलब्ध कराने हेतु क्या प्रबन्ध किये गये हैं

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. लेंका) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् देश के विभिन्न कृषि जलवायवीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त तकनीकों के विकास के लिए अनुसंधान के एक नेटवर्क के माध्यम से बढ़ावा दे रही है । इसके अंतर्गत अनुसंधान अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनायें, तदर्थ अनुसंधान प्रायोजनायें और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजनायें और सहयोगी के रूप में राज्य कृषि विश्वविद्यालय आते हैं । विभिन्न खाद्य फसलों की अधिक पैदावार देने वाली किस्में विकसित की गई हैं और संकर अनुसंधान, प्रजनक बीज के उत्पादन, जर्म-प्लाज्म के संरक्षण, जैविक और अजैविक दबाव रोधी सुधरी किस्मों के विकास पर बल दिया जा रहा है।

(ग) कृषि विज्ञान केन्द्रों, राष्ट्रीय प्रदर्शनों, व्यावहारिक अनुसंधान प्रायोजनाओं और प्रयोगशालाओं से खेत तक कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को विकसित की गई टेक्नोलोजी उपलब्ध कराई जा रही है।

सहकारी भंडारण परियोजनाओं को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा दी गई सहायता

2447. श्री कमीज जोषी :
चौधरी हरि सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकारी भण्डागारण परियोजनाओं को राज्य वार कितनी-कितनी धनराशि की सहायता प्रदान की गई है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अलग-अलग राज्यों में कितने-कितने भंडागारों का निर्माण किया गया है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस परियोजना के अधीन कितने भांडागारों के निर्माण का प्रस्ताव है ?

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस परियोजना के अधीन कितने गोदामों के निर्माण का प्रस्ताव है ?

कृषि विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुस्ता-पल्लीराजबन्धम) : : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय परियोजना के अधीन बिहार सरकार को 642.109 लाख रुपये की राशि प्रदान की है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपए में)

वर्ष	दी गई राशि
1989-90 . . .	170.90
1990-91 . . .	273.29
1991-92 . . .	197.90
योग :	642.090

पिछले तीन वर्षों में यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता प्राप्त भण्डारण परियोजना के अधीन कोई दूसरा राज्य शामिल नहीं है ।